भारतीय जनता पार्टी

केन्द्रीय कार्यालय
11, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

दिनांक : 26 अप्रैल, 2013

सीएजी पर हमले के लिए जयराम रमेश माफी मांगे

भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान, सांसद द्वारा मनरेगा पर सीएजी रिपोर्ट तथा श्री जयराम रमेश द्वारा सीएजी के विरूद्ध दिए बयान पर प्रेस वक्तव्य

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मनरेगा पर दिए गए सीएजी रिपोर्ट को ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश ने खारिज करने के अंदाज में महत्व न देते हुए इसे मात्र ''फाइनेंशियल ऑडिट'' कहा तथा कहा है कि यह रिपोर्ट ''परफॉर्मेंस ऑडिट'' नहीं है। आये दिन उजागर होते हुए घोटाले के संदर्भ में क्या यूपीए सरकार अब यह कहना चाहती है कि वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार में कोई संबंध नहीं है। इससे तो ऐसा लगता है कि जनता के पैसों को लूटने का खुला लाईसेंस अब यूपीए सरकार बांट रही है। इससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि श्री जयराम रमेश ने इसके अलावा कहा है कि यह, फाइनेंशियल ऑडिट था, परफॉर्मेस आडिट, या फॉरेंसिक ऑडिट नहीं... पिछले तीस वर्षो में मैंने कभी भी सीएजी को कोई सकारात्मक रिपोर्ट देते हुए नहीं देखा।'' यह सीएजी जैसे संस्थान पर एक खुला हमला है जिससे गंभीर प्रश्न उठते हैं कि यूपीए सरकार संवैधानिक एवं निष्पक्ष संस्थाओं का आदर करना चाहती है या नहीं। यह एक विडंबना ही है कि जब जयराम रमेश सीएजी की रिपोर्ट को खारिज कर रहे होते हैं तब साथ ही सीएजी को जांच करने के लिए आग्रह करने का श्रेय भी बटोरनें से नही चूकना चाहते। यदि उन्हें पता था कि सीएजी को सकारात्मक रिपोर्ट देने की आदत नहीं तब उन्होंने उनसे जांच का आग्रह ही क्यो किया? श्री जयराम रमेश को सीएजी की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए तत्काल माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का

उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि, ''कमियां निकालना सीएजी का काम है और यदि वे कमियां नहीं गिना पाये तो इसका मतलब है कि वे अपना काम ठीक से नहीं कर रहे।'' क्या सीएजी जैसी संस्था अपने दायित्व का निर्वहन केवल इसलिए करती है ताकि वह दिखा सके कि वह कुछ कर रही है? इस तरह के वक्तव्य अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए।

सीएजी रिपोर्ट को केन्द्र की कांग्रेसनीत यूपीए सरकार एवं सभी राज्य सरकारों को पूरी गम्भीरता से लेनी चाहिए। इस रिपोर्ट से पूरे देश को झटका लगा है, क्योंकि यह अपेक्षा की जा रही थी कि मनरेगा से अर्थव्यवस्था का पूरा परिदृश्य बदल जायेगा एवं गरीब तबकों को इससे भारी फायदा होगा। सीएजी रिपोर्ट से यह पता चलता है कि स्वीकृत कार्यो का मात्र 30 प्रतिशत कार्य ही पूरा किया जा सका और प्रति घर सौ दिन कार्य के स्थान पर मात्र 43 दिन कार्य ही उपलब्ध कराया जा सका। इसके अलावा देश में विभिन्न भागों में बडी संख्या में मजदूरों के फर्जी नामों का पाया जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि गरीबों के नाम पर भारी लूट का कारोबार फल–फूल रहा है। सीएजी ने मनरेगा के कार्यान्वयन में भारी अनियमितताएं, आबंटित राशि का मजदूरों के फर्जी नामों पर भारी लूट, महंगी कार्यप्रणाली, भुगतान में विलम्ब, रिकार्ड में अनियमितताएं जैसे बडे सवाल अपनी रिपोर्ट में उठाये है। सीएजी ने यह भी कहा है कि अनेक राज्यों में अधिकारियों द्वारा इस पूरी योजना पर कब्जा जमा लिया गया है तथा जनता के पैसों की भारी लूट मची हुई है।

अब तक सीएजी ने अनेक गंभीर सवाल उठाए है और अनेक घोटालों का पर्दाफाश किया हैं। JNURM में अनियमिततायें, खाद घोटाला, किसानों के ऋण माफी में घोटाला और अब मनरेगा में लूट का कारोबार–इन सबके बावजूद सीएजी यूपीए सरकार को सुधारात्मक कदम उठाने को बाध्य नहीं कर पाई है। इन कमियों को दूर करने एवं सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने के स्थान पर कांग्रेसनीत यूपीए सरकार सीएजी के विरूद्ध दुष्प्रचार करने में लगी है और इसके रिपोर्ट में मीन–मेख निकालने में अपना वक्त बर्बाद कर रही है। श्री जयराम रमेश का वक्तव्य कोई नई बात नहीं है। इससे पूर्व भी प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री श्री वी0 नारायण स्वामी ने बहुसदस्यीय सीएजी की बात पिछले नवम्बर

में उठाई थी। कांग्रेसनीत यूपीए सरकार को अपना आत्मावलोकन सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए ताकि जनता की गाड़ी पसीने से कमाया गया धन को इस तरह से लूटा नही जा सके तथा करदाताओं का धन इस देश में भविष्य के निर्माण में लगे । हम यह मांग करते है कि कांग्रेसनीत यूपीए सरकार मनरेगा पर तत्काल एक विस्तृत वक्तव्य दे तथा शीघ्रातिशीघ्र उचित दिशा में कार्रवाई करे ताकि इस योजना के नाम पर लूट को रोका जा सके। हम यह भी मांग करते है कि श्री जयराम रमेश तत्काल माफी मांगे तथा कांग्रेसी नेता एवं यूपीए सरकार के मंत्री भविष्य में सीएजी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं पर हमला करने से बाज आएं।

¼/keZsUnz iz/kku½
lkaln
jk"Vªh; egkea=h
Hkktik